क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 32, रविवार, 24 फरवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार-समावार

असम: कार्बी आंगलोंग में उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

दीफू(असम).

मध्य असम के कार्बी आंगलोंग जिले में पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी-लोंगरी (पीडीसीके) के एक कट्टर उग्रवादी को हथियार और गोला-बारूद के साथ शुक्रवार (22 फरवरी) को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. सेना और जिले के बोरलंगफर इलाके की पुलिस ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया.

कार्बी आंगलोंग जिला के पुलिस अधीक्षक गौरव उपाध्याय ने बताया कि बोरलंगफर इलाके में पीडीसीके उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में खूफिया सूचना मिलने पर सेना और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने अभियान शुरू किया और डोलामारा थाना के अन्तर्गत बोकराम तोकबी गांव के वेल्सन तेरंग उर्फ मोंगवे तेरंग के रूप में पहचान किए गए उग्रवादी को धर दबोचा.

एसपी ने बताया कि वेल्सन पूर्व में कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स (केपीएलटी) का एक कट्टर सदस्य था और जबरन वसूली, अपहरण सहित अन्य मामलों में शामिल था. उसे पहले भी 2013 और 2015 में गिरफ्तार किया गया था. उपाध्याय ने बताया कि जमानत मिलने के बाद वेल्सन पीडीसीके में शामिल हो गया और जबरन वसूली और उग्रवादी संगठन में युवाओं की भर्ती का काम करने लगा.

उन्होंने बताया कि पिछले साल वेल्सन ने अपने सहयोगियों के साथ बोकराम तोकबी गांव में पुलिस की एक टीम पर हमला भी किया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

लोकसभा चुनाव 2019 दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव हो सकता है: चुनाव विशेषज्ञ

वाशिंगटन:

अमेरिका स्थित एक चुनाव विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत में आगामी आम चुनाव भारत के इतिहास में और किसी भी लोकतांत्रिक देश के सबसे खर्चीले चुनावों में से एक होगा. भारत का चुनाव आयोग जल्द ही 543 सदस्यीय लोकसभा के लिये चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है.

कारनीज एंडोमेंट फोर इंटरनेशनल पीस थिंकटैंक में सीनियर फेलो तथा दक्षिण एशिया कार्यक्रम के निदेशक मिलन वैष्णव ने मीडिया को बताया कि 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तथा कांग्रेस चुनावों में 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आया था. अगर भारत में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में पांच अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे तो 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा आसानी से पार हो सकता है, ऐसा हुआ तो यह दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव साबित होगा.

लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिये 27 फरवरी को बैठक करेंगे विपक्षी दल - सूत्र

विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव के लिये न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानि बीजेपी को हराने की साझा रणनीति को लेकर 27 फरवरी को दिल्ली में अहम बैठक करेंगे. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. 13 फरवरी को कांग्रेस समेत छह मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं के बीच हुई बैठक में साझा रणनीति बनाने का फैसला लिया गया था. इसके बाद ऐलान किया गया था कि लोकसभा चुनाव के लिये चुनाव पूर्व गठनबंधन और न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाएगा.

उस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख फारुक अब्दुल्ला समेत अन्य नेताओं ने शिरकत की थी. सूत्रों के मुताबिक चुनाव पूर्व गठबंधन का समर्थन नहीं करने वाले वाम दलों के बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद नहीं है.

ममता, केजरीवाल के बाद फिर एक साथ दिखेगा पूरा विपक्ष, कांग्रेस भी हो सकती है शामिल!

नई दिल्ली:

विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव के लिये न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानि भाजपा को हराने की साझा रणनीति को लेकर 27 फरवरी को दिल्ली में अहम बैठक करेंगे. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

13 फरवरी को कांग्रेस समेत छह मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं के बीच हुई बैठक में साझा रणनीति बनाने का फैसला लिया गया था. इसके बाद ऐलान किया गया था कि लोकसभा चुनाव के लिये चुनाव पूर्व गठनबंधन और न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाएगा. उस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख फारुक अब्दुल्ला समेत अन्य नेताओं ने शिरकत की थी.

सूत्रों के मुताबिक चुनाव पूर्व गठबंधन का समर्थन नहीं करने वाले वाम दलों के बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद नहीं है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि वह याचिका में आरोपी के तौर पर उन्हें तलब किए जाने या नहीं किए जाने पर दो मार्च को अपना फैसला सुनाएंगे.

विवेक ने अपनी याचिका में कहा था कि पत्रिका और रमेश ने ''उनके पिता से बदला लेने के लिए'' उन्हें ''जानूबझकर बदनाम''करने की कोशिश की.

'द कैरवैन' ने आरोप लगाया था कि विवेक डोभाल ''केमैन द्वीप में एक हेज फंड चलाते हैं'' जो ''कालाधन छुपाने के लिए पनाहगाह'' के रूप में जाना जाता है. शिकायत के अनुसार रमेश ने 17 जनवरी को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके लेख में कहे ''निराधार तथ्यों'' को दोहराया था.

पाक कैदी कर रहे दूसरों को गुमराह, J&K सरकार ने SC से तिहाड़ जेल शिफ्ट करने की मांग की

नई दिल्ली .

पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों को लेकर भी सरकारें सतर्क हैं. इसी के तहत जम्मू और कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि जम्मू की जेल में बंद सात पाकिस्तानी कैदियों को सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. जम्मू कश्मीर सरकार ने आरोप लगाया है कि ये कैदी स्थानीय कैदियों को गुमराह कर रहे हैं.

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने जम्मू कश्मीर सरकार की याचिका पर केन्द्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. राज्य सरकार के वकील शोएब आलम ने कहा कि विभिन्न संगठनों के इन आतंकवादियों को जम्मू जेल से बाहर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे स्थानीय कैदियों को गुमराह कर रहे हैं.

राज्य सरकार का कहना है कि यदि तिहाड़ जेल में भेजना संभव नहीं हो तो उन्हें हरियाणा और पंजाब की दूसरी कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में स्थानांतरित किया जा सकता है. इस पर पीठ ने कहा कि सारे मामले पर विचार किया जाएगा. साथ ही उसने राज्य सरकार के वकील से कहा कि वह इन पाकिस्तानी आतंकियों पर भी नोटिस की प्रति की तामील सुनिश्चित करे.

जम्मू कश्मीर सरकार ने 14 फरवरी को हुये पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने की घटना के बाद लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी जाहिद फारूक को जम्मू जेल से अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिये शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.

फारूक को 19 मई, 2016 को सुरक्षा बलों ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह सीमा पर लगी बाड़ से घुसने का प्रयास कर रहा था. राज्य सरकार ने कहा था कि प्राप्त खुफिया जानकारी से संकेत मिला है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के आतंकवादी जेल में बंद दूसरे कैदियों को गुमराह कर रहे हैं.

राज्य सरकार के अनुसार उसे यह भी पता चला है कि कैदियों और दूसरे लोगों को काफी स्थानीय समर्थन प्राप्त है और इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें आतंक से जुड़ी गतिविधियां करने के लिए सूचनाएं, संसाधन और दूसरी मदद भी मिल रही हो.

ममता 'दीदी' ने साधा निशाना, कहा- 'देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है BJP'

एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से बीजेपी पर हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे अपनी आस्था के आधार पर अमानवीय धर्म बनाने की कोशिश कर रहे है.

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि देश में विभाजनकारी राजनीति के आधार पर 'अमानवीय' धर्म लाने का प्रयास किया जा रहा है. बनर्जी ने अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस पर गुरुवार (21 फरवरी) को आयोजित एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वे अपनी आस्था के आधार पर अमानवीय धर्म बनाने की कोशिश कर रहे है. वे यह फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में कौन रहेगा और कौन यहां से जाएगा ? वे यह निर्णय ले रहे हैं कि लोग किस भाषा में बात करेंगे, लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे. वे देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कुछ लोग अपनी इच्छानुसार एक कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे. हम विभाजनकारी राजनीति के इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करते. उन्होंने कहा कि हम एकजुट भारत चाहते हैं. आइए एकता के बारे में सोचें और बात करें. विभाजन करो और शासन करो की कोई नीति नहीं होनी चाहिए.

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख बनर्जी ने कहा कि वह लोगों को उनके धर्म, जाति या सम्प्रदाय के आधार पर बांटने की राजनीति में भरोसा नहीं करतीं. उन्होंने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कोलकाता में कश्मीरी मेडिकल छात्रों को मिली धमकियों की भी आलोचना की. उन्होंने लोगों से कहा कि वे देश को बांटने के कदम के विरोध में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें.

UPA-2 ने नहीं किया था बेहतर काम इसलिए हुई थी हार: रघुवंश प्रसाद सिंह

नई दिल्ली:

बिहार महागठबंधन में सीटों के मसले से लेकर नेतृत्व तक की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. जहां सभी छोटे से लेकर बड़े दल सीटों की दावेदारी कर रहे हैं. वहीं, आरजेडी की ओर से कहा गया है कि सीट शेयरिंग नहीं हुई तो किसी की भी दावेदारी का कोई मतलब नहीं है. इस बीच आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि छोटे दल अपने नेतओं को खुश करने के लिए टिकट मांग रहे हैं. साथ ही कहा यूपीए-2 ने बेहतर काम नहीं किया था इसलिए हार का सामना करना पड़ा था.

रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि यूपीए-2 ने बेहतर काम किया होता तो उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ता. उन्होंने कहा कि हार का मुख्य कारण यूपीए-2 के काम करने का ढंग जिम्मेदार था. अगर सरकार की मोनेटरिंग की गई होती तो ऐसा नहीं होता. यूपीए-2 में सरकार को कोई वॉच नहीं कर रहा था. और इसकी मोनेटरिंग भी नहीं का जा रही थी. जिससे हार का सामना करना पड़ा.

वहीं उन्हें पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भी मालूम नहीं है कि सरकार कैसे चलाई जाती है. सरकार में रहकर अबतक वह झूठ ही बोल रहे हैं. उनके कारण लोगों का काफी परेशानियां झेलनी पड़ी है. रघुवंश सिंह ने नोटबंदी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि 500-1000 के नोट बंद ही कर दिए गए तो फिर 500-2000 का नोट क्यों बाजार में लाया गया.रघुवंश प्रसाद सिंह ने यूपीए-2 के कार्यकाल को सही नहीं ठहराया. हालांकि उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कांग्रेस का रहना जरूरी है. उन्होंने कहा कि 2009 में कांग्रेस को छोड़कर गलती हो चुकी है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. वह यूपी में हुई गलती को बिहार में नहीं दोहराएंगे.

वहीं, जीतनराम मांझी के सीटों के दावों को लेकर कहा कि उन्हें हमने पहले ही कहा था कि अपनी छोटी पार्टी को मर्ज कर दीजिए और कॉमन सिंबल पर चुनाव लड़ें. लेकिन छोटे दल अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा. महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है बात करने पर सभी चीजें ठीक हो जाएगी.

वहीं, उन्होंने सवर्ण आरक्षण को लेकर भी कहा कि आरजेडी कभी इसके विरोध में नहीं आई है. हमारे 2014 के मेनिफेस्टो में भी यह बात लिखी है. उन्होंने कहा कि मनोज झा ने संसद में क्या बोले उसका कोई मतलब नहीं है. इस पर कोई क्या बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि मेनिफेस्टो में लिखा है तो किसी के भी बोलने से कुछ भी नहीं होगा. आरजेडी सवर्णों की हितैषी है.

यूपी के बाद असम में दिखा जहरीली शराब का प्रकोप, 18 मजदूरों की मौत

असम के घोलघाट जिला में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो गी है. जबकि 47 लोगों की हालात नाजुक बताई जा रही है.

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के बाद असम में जहरीली शराब का प्रकोप देखने को मिला है. असम के घोलघाट जिला में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो गी है. जबकि 47 लोगों की हालात नाजुक बताई जा रही है. जहरीली शराब पीने से हुई मौत में 14 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं. वहीं, नाजुक हालात वाले लोगों को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफेर किया गया हैं.

टी-इस्टेट में कार्यरत हैं सभी

जहरीली शराब पीने से जिन 18 लोगों की मौत हुई है, वह सभी सालमरा टी इस्टेट में कार्यरत हैं. एक साथ इतने मजदूरों के शराब पीने से बीमार पड़ने पर लोगों का गुस्सा फूटा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हलमिरा चाय बागान में लोगों ने जहरीली शराब पी थी. इसे शहर के बाहर से लाया गया था. स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में खुलेआम जहरीली शराब बेची रही है. इसके बाबजूद आबकारी विभाग और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी इस पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है की अगर आबकारी विभाग और जिला पुलिस देशी ज़हरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ करवाई करती तो ये घटना नहीं घटती. कई लोगों का कहना है कि उन्होंने आबकारी विभाग और पुलिस में कई बार शराब बेचने की शिकायत दर्ज कराई थी, इसके बाद भी उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

वहीं, दूसरी तरफ घोलघाट जिला प्रसाशन ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं. अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट का कहना है कि हमने घटना के सन्दर्भ में जांच की आदेश जारी कर दिए हैं और देशी शराब पीकर मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए भी सरकार से मानवीय आधार पर मदद राशि देने की अनुरोध की है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह की करवाई की जा सकती हैं, बहरहाल लोगों से शान्ति बहाल रखने की अपील की हैं और देशी शराब बेचने वालों को गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिया गए हैं.

25 फरवरी से शुरू होगा महाराष्ट का विधानसभा सत्र, इन मुद्दों को उठा सकता है विपक्ष

छह दिवसीय सत्र का आरंभ राज्य विधानसभा के राज्यपाल सी विद्यासागर राव के संबोधन से होगा. अनुपूरक मांगें 26 फरवरी को पेश की जाएंगी.

मुंबई .

महाराष्ट्र विधानसभा का छह दिवसीय बजट सत्र 25 फरवरी को आरंभ होगा और लोकसभा चुनावों से पहले यह राज्य का आखिरी. सत्र होगा जिसके मद्देनजर इसके हंगामेदार होने की आशका है. इसके शुरुआत में तीन सप्ताह चलने की योजना थी और इसे 18 फरवरी को आरंभ होना था लेकिन 2019 आम चुनावों के लिए मार्च में आचार संहित लागू होने की संभावना के मद्देनजर इसकी अवधि कम कर दी गई.

महज 6 दिनों के लिए होगा सत्र

छह दिवसीय सत्र का आरंभ राज्य विधानसभा के राज्यपाल सी विद्यासागर राव के संबोधन से होगा. अनुपूरक मांगें 26 फरवरी को पेश की जाएंगी और उसी दिन पारित की जाएंगी जबकि लेखानुदान 27 फरवरी को पेश किया जाएगा. अंतरिम बजट 28 फरवरी को बहस के बाद पारित होगा. लेखानुदान में कृषि पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है. राज्य में सूखे की स्थिति पर दो दिवसीय बहस एक-दो मार्च को होगी.

विपक्ष उठा सकता है ये मुद्दे

विपक्षी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राज्य में सूखे, किसानों की आत्महत्या और कानून-व्यवस्था संबंधी मामलों को लेकर भाजपा-शिवसेना गठबंधन को घेरने की कोशिश करेंगी.2014 में सत्ता में आने के बाद से अधिकतर मामलों पर लगातार एक दूसरे पर निशाना साधने वाले सत्तारूढ़ सहयोगियों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हाल में गठबंधन किया है.

हालांकि दोनों दलों में मतभेद अब भी बरकरार हैं, क्योंकि शिवसेना की मांग है कि दोनों पार्टियों के नेता ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री रहें. विधानसभा में जो नए विधेयक पेश किए जाएंगे, उनमें पुणे के अम्बी तालेगांव में डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय और मुंबई के विद्याविहार में के जी सोमैया विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक भी शामिल है.

राज्य के संसदीय मामलों के विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि छोटे समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि राजस्व संहिता में भी संशोधन का विधेयक पाइपलाइन में है. इसके अलावा लोक न्यास अधिनियम में भी संशोधन का महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र के दौरान पेश हो सकता है.

संपादकीय

शोषण के बहुचर्चित मामले

अनिल अम्बानी के मामले में उसने अपने तेवर अपेक्षाकृत कड़े रखे और सख्त सजाएं सजा दी हैं। हां, उसने इन दोनों ही मामलों में दोषियों के बिना शर्त माफीनामे के साथ एक जैसा सलूक किया, जिसमें न सिर्फ उन्हें पूरी तरह नामंजूर कर दिया बल्कि इस बात को गम्भीरता से लिया कि दोषियों ने अनजाने अथवा विवशता में नहीं, जानबूझकर उसके आदेश की अवज्ञा की। यहां तक कि उसके समक्ष दी गई अंडरटेकिंग पर अमल नहीं किया और उससे ऐसा झूठ बोला जिससे न्यायिक प्रशासन प्रभावित हुआ। इन दो फैसलों के बाद कहा जा रहा है कि अब न्यायालय अपने आदेशों का पालन किये जाने को लेकर पहले की अपेक्षा ज्यादा गम्भीर हो गया है।

सतीश पेडणोकर

12 फरवरी को ही सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में संवासिनियों के बलात्कार व शोषण के बहुचर्चित मामले से सम्बन्धित अपने आदेश की अवमानना को लेकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व कार्यवाहक निदेशक एम. नागेश्वर राव और विधि सलाहकार एस. भासुरम को एक-एक लाख रुपये के जुर्माने और फैसले के दिन न्यायालय के उठने तक उसके एक कोने में बैठे रहने की सजा सुनाई थी। दरअसल, एम. नागेश्वर राव ने न्यायालय की मनाही के बावजूद उक्त मामले की जांच कर रहे अधिकारी का तबादला कर दिया था। अब न्यायालय ने एक और चर्चित मामले में एरिक्सन इंडिया नामक कम्पनी द्वारा दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए रिलायंस कम्युनिकेशन के अध्यक्ष और मशहूर उद्योगपति अनिल अम्बानी को उनके समूह की दो अन्य कम्पनियों के अध्यक्षों सतीश सेठ व छाया विरानी के साथ तीन-तीन महीने की जेल और एक-एक करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उसने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि चार हफ्ते में उसकी रजिस्ट्री में न जमा कराने पर दोषियों को एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अलबत्ता, उसने यह गुंजाइश रखी है कि उसके आदेश के मुताबिक याची कम्पनी को चार हफ्तों में 453 करोड़ रुपयों की अदायगी करके दोषी तीन महीने की सजा से निजात पा सकते हैं। इस सिलसिले में यह भी गौरतलब है कि एम. नागेश्वर राव के मामले में जहां न्यायालय ने प्रतीकात्मक सजा से काम लिया था, अनिल अम्बानी के मामले में उसने अपने तेवर अपेक्षाकृत कड़े रखे और सख्त सजाएं सजा दी हैं। हां, उसने इन दोनों ही मामलों में दोषियों के बिना शर्त माफीनामे के साथ एक जैसा सलूक किया, जिसमें न सिर्फ उन्हें पूरी तरह नामंजूर कर दिया बल्कि इस बात को गम्भीरता से लिया कि दोषियों ने अनजाने अथवा विवशता में नहीं, जानबूझकर उसके आदेश की अवज्ञा की। यहां तक कि उसके समक्ष दी गई अंडरटेकिंग पर अमल नहीं किया और उससे ऐसा झूठ बोला जिससे न्यायिक प्रशासन प्रभावित हुआ। इन दो फैसलों के बाद कहा जा रहा है कि अब न्यायालय अपने आदेशों का पालन किये जाने को लेकर पहले की अपेक्षा ज्यादा गम्भीर हो गया है। इससे पहले न्यायालय ने अयोध्या में विवादित ढांचे की सुरक्षा का हलफनामा देकर उसका खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करने के मामले में उसके बहुत संवेदनशील होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दिन भर की हिरासत की सजा देकर ही ''बख्श' दिया था। इसी तरह, 2006 में महाराष्ट्र के एक मामले में वहां के उस वक्त के परिवहन मंत्री सुरूप सिंह नायक और अवर मुख्य सचिव अशोक खोट को एक-एक महीने की सजा ही दी थी। थोड़ा और पहले जाएं तो 1983 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की याचिका पर उसने श्रमिकों के संदर्भ में सरकार को 24 निर्देश दिये थे, जो उनको भोजन, आवास, स्वच्छ माहौल और उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित थे। सरकारी अमले की काहिली से इनमें से एक का भी पालन नहीं किया गया। तिस पर दीदा-दिलेरी ऐसी कि न्यायालय द्वारा रिपोर्ट मांगी गई, तो भारत सरकार के श्रम एवं कल्याण महानिदेशक ने यह बात उसको साफ-साफ बता भी दी। इसके बावजूद मोर्चे के स्वामी अग्निवेश ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए अवमानना याचिका दायर की, तो पहले तो वह सूचीबद्ध ही नहीं हुई, फिर हुई तो भी उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। स्वाभाविक ही उस मामले में आज तक किसी को सजा नहीं हुई। जानकारों की मानें तो न्यायिक आदेशों की अवमानना के ज्यादातर मामलों में दोषियों को इसलिए सजा नहीं हो पाती क्योंकि उनमें आदेश का सीधा-सीधा उल्लंघन नहीं किया गया होता और अवमानना याचिका दायर होने पर वे आदेश को लम्बे समय तक लागू न किये जाने के मामले सिद्ध होते हैं। इसके बाद अवमानना के अभियुक्त सम्बन्धित आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दायर कर देते हैं तो न्यायालय न उनसे अनुपालन में देरी के लिए कैफियत तलब करता है और न उन्हें दंडित करने की जरूरत ही समझता है। यह भी नहीं देखता कि आदेश से प्रभावित होने वाले को उनके ही कारण अदालत का दरवाजा खटखटाकर अवमानना याचिका दायर करने को मजबूर होना पड़ा और उसके बाद ही आदेश का अनुपालन सम्भव हुआ। कायदे से यह देखा जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार अनुपालन में अक्षम्य देरी के कारण सम्बन्धित आदेश का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कई बार तो अवमानना याचिकाएं दायर न होने से पता ही नहीं चलता कि उसका अनुपालन हुआ भी या नहीं। ऐसे में अपने हुक्मों की उदूलियों को लेकर न्यायालय का रवैया सचमुच बदला और गम्भीर हुआ है तो यह ठीक ही है। देश में कानून का शासन बनाये रखना है, जो बनाये ही रखना है क्योंकि न हम राजाओं के दौर में वापस जा सकते हैं और न अराजकता व अव्यवस्था को गले लगाने के खतरे उठा सकते हैं तो न्यायिक आदेशों का हर हाल में पालन सुनिश्चित करना होगा। किसी को भी इस हिमाकत की इजाजत नहीं देनी होगी कि वह अपनी पहुंच या प्रभुत्व के गुमान में उसे ठेंगे पर रखे और उम्मीद करे कि फंस भी जायेगा तो एक औपचारिक माफीनामा देकर छूट जायेगा। अनिल अम्बानी के संदर्भ में तो इसका इसलिए भी महत्त्व है कि इन दिनों उनका नाम देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चहेतों में शुमार किया जाता है। एरिक्सन की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में सहायक रजिस्ट्रार पद पर तैनात मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवर्ती ने उसका एक आदेश उसकी वेबसाइट पर इस तरह बदलकर अपलोड किया, जिससे लगे कि अनिल को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश होने की जरूरत नहीं है। बाद में न्यायालय ने अपने इन दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर उनके प्रपंच की सजा दी तो स्वाभाविक ही धारणा बनी कि उन्हें अनिल के इंगित पर किये गये अपनी स्थिति के दुरुपयोग की सजा मिली है। इन हालात में न्यायालय के ताजा फैसले के बाद उम्मीद की जा सकती है कि कोई कितना भी ''शक्तिशाली' क्यों न हो, ''समरथ को नहिं दोष गोसाई' के सिद्धांत पर न्यायिक आदेशों को आंखें नहीं दिखा सकेगा। इससे न्यायिक आदेशों की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी और उसकी अवमानना करने के लोगों के मंसूबों पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा।

अर्थव्यवस्था और सामान्य जीवन

नितिन गडकरी का यह वक्तव्य काफी गंभीर है कि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत नदियों से अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने का फैसला किया है। पाकिस्तान के लिए इस फैसले के निहितार्थ काफी गहरे हैं। जब भी बड़े आतंकवादी हमले हुए और पाकिस्तान का नाम आया, भारत में यह मांग निश्चित उठती थी कि उसकी ओर जाने वाली नदियों का पानी रोक दिया जाए। गडकरी का ट्विट साबित करता है कि सरकार ने केवल फैसला नहीं किया, इस पर काम भी शुरू है। भारत ऐसा कर पाया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सामान्य जीवन के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। गडकरी के वक्तव्य में वाकई पानी रोकने के लिए पूरी कार्ययोजना का विवरण है। इसमें कहा गया है कि हम पूर्वी नदियों की धारा को बदल देंगे और उसे जम्मू-कश्मीर और पंजाब में अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए बांध बनाने की दिशा में कार्रवाई आरंभ हो गई है। निस्संदेह, फैसले को पूरी तरह अमल में लाने में कई वर्ष लग सकते हैं। आखिर जल का प्रवाह रोकने के लिए 100 मीटर की ऊंचाई वाले बांध बनाने होंगे। किंतु रावी नदी पर शाहपुर कांडी में बांध का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके अलावा, यूजेएच परियोजना में भारत के हिस्से का पानी जमा किया जाएगा और उसका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर के लिए होगा। शेष बचा पानी दूसरी रावी-व्यास लिंक के जरिये देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जाएगा। 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पश्चिम की नदियों-सिंधु, झेलम और चेनाब-का जल पाकिस्तान को दिया गया, जबकि पूर्वी नदियों-रावी, ब्यास और सतलुज-का जल भारत को दिया गया। बावजूद इसके भारत से रावी ब्यास और सतलुज का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। जब 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक भाषण में कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे तो उसे कम ही लोगों ने गंभीरता से लिया था। पाकिस्तान की पन बिजली और सिंचाई परियोजनाएं इन नदियों के पानी पर भी निर्भर हैं। इसलिए इसका सीधा असर होगा। वास्तव में पाकिस्तान का 47 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित होगा। जो देश हमारे प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं, उसके प्रति हम संवेदनशील क्यों रहें? पूरा देश इस फैसले का स्वागत करेगा। पाकिस्तान को सबक देने के कई कदमों में यह स्थायी महत्त्व का एक अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

प्रशासनिक सेवा को त्याग

पुलवामा हमले से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के जवानों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात अर्धसैनिक बलों के जवान छुट्टी पर जाने के लिए, छुट्टी से ड्यूटी पर लौटते वक्त, तबादला अब वाणिज्यिक उड़ानों का इस्तेमाल कर सकेंगे। पुलवामा हमले के बाद यह सवाल उठाए जा रहे थे कि जवानों का इतना बड़ा काफिला अगर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुआ है तो, इसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और इन जवानों की मुकम्मल सुरक्षा इंतजाम में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? करीब हफ्ते भर बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत फैसला लिया है। आए दिन सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की घटना के बाद इस तरह का निर्णय निहायत जरूरी था। इस कदम से अर्धसैनिक बलों के कुल 7.8 लाख जवानों को फौरी तौर पर हवाईजहाज से आने-जाने की इजाजत मिल गई है। निश्चित तौर पर इस तरह के कदम सराहनीय हैं और इससे अर्धसैनिक बलों के जवानों का मनोबल मजबूत होगा। वैसे तो इसे सिर्फ कश्मीर के लिए लागू किया गया है, मगर जहां-जहां भी इस तरह के कदम उठाने की गुंजाइश है या सुरक्षा बलों पर खतरा है; वहां भी ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। एक और कदम जो जवानों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, वह है काफिले के मूवमेंट के वक्त ट्रैफिक बंद रहेगा। यानी जवानों के आने-जाने के समय आम लोगों को अपने वाहन लाने की इस्तेमाल न मिले। इस फैसले से आम जनता को भले कुछ समय के लिए कठिनाई होगी। इस तरह की सुविधा देने को लेकर अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। चूंकि जवान बेहद दुरूह हालात में ड्यूटी करते हैं, लिहाजा उन्हें आराम देने और तरोताजा रखने के लिए इस तरह की सुविधा मुहैया करानी ही होगी। सो, जवानों और कमांडिंग अधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को साल भर में दिए जाने वाले आकस्मिक अवकाश (सीएल) की संख्या में 13 दिनों की वृद्धि करना चाहता है। कुल मिलाकर जवानों की सुरक्षा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए और इस दिशा में उठाए गए कदमों से कई मोर्चों पर सफलता भी मिलेगी।

चलते चलते

लड़ाई में पॉलिटिक्स

नेशनल जियोग्राफिक की फिल्म के लिए शूटिंग क्यों करा रहे थे? नाव में बैठकर, कैमरेवालों को घड़ियाल दर्शन क्यों करा रहे थे? ये आतंकवाद से लड़ाई में पॉलिटिक्स घुसाने वाले क्या जानें एक सच्चे कलाकार के कमिटमेंट की कीमत-द शो मस्ट गो ऑन। एक बार कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं।

देखी, विपक्ष वालों की घोर एंटीनेशनलगिर्दी देखी। कह रहे हैं कि पुलवामा के आतंकी हमले के बाद, पीएम जी जिम काब्रेट के जंगल में मंगल क्यों मना रहे थे? नेशनल जियोग्राफिक की फिल्म के लिए शूटिंग क्यों करा रहे थे? नाव में बैठकर, कैमरेवालों को घड़ियाल दर्शन क्यों करा रहे थे? ये आतंकवाद से लड़ाई में पॉलिटिक्स घुसाने वाले क्या जानें एक सच्चे कलाकार के कमिटमेंट की कीमत-द शो मस्ट गो ऑन। एक बार कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं। सलमान खान ने कमिटमेंट का जो ऊंचा मेयार कायम कर दिया है, उसे कौन नहीं जानता है। पीएम जी का कमिटमेंट इस पैमाने से जरा सा भी हल्का पड़ता हो तो विपक्ष वाले बोलें। कश्मीर की घाटी में तो मौसम दोपहर के बाद खराब हुआ था, दिल्ली और बाकी देश में तो मौसम सुबह से ही खराब था। पर कमिटमेंट तो कमिटमेंट ठहरा। मौसम की कोई खराबी पीएम जी को भला रोक सकती थी? खराब मौसम में भी उड़कर उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड ही नहीं पहुंचे, जिम कॉब्रेट भी पहुंच गए, वह भी बिना किसी शोर-शराबे के। हाथियों, टाइगरों को ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया और उनकी खबर भी ले ली। टाइगरों की खबर लेना तो राष्ट्रहित में बहुत ही जरूरी था। वर्ना सड़क से लेकर बजट तक गोरक्षा ही गोरक्षा का शोर होने से पड़ोसियों को यह नहीं लगने लगता है कि अपना पीएम भी गऊ है, शेर नहीं। बारिश थी, फिर भी नाव में घड़ियालों की खबर भी लेने पहुंच गए। नैनीताल से पुलवामा तक के खराब मौसम में भी, एक-एक कमिटमेंट पूरा किया। खुद नहीं पहुंच सके तो क्या, रुद्रप्रयाग में जनसभा को फोन से संबोधित किया। कमिटमेंट था, सो परियोजनाओं का उद्घाटन भी फोन से ही किया। मौसम खराब था, पर आयोजन करने वालों का मजा भी खराब नहीं होने दिया; पुलवामा का दर्द दिल में ही रखा। इतने सारे कमिटमेंटों के बीच पीएम जी फिल्म शूटिंग का ही कमिटमेंट पूरा नहीं करते, तो क्या सारी दुनिया को क्या संदेश जाता-आतंकवाद की वजह से भारत रुक गया। ना मंजूर। द शो मस्ट गो ऑन।

सत्संग

अनुभव ही सत्य

पना अनुभव ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। जिस बोलने के साथ यह आग्रह होता है कि मैं कहता हूं, उस पर इसलिए विास करो क्योंकि मैं कहता हूं। जिस बोलने के लिए श्रद्धा की मांग की जाती है-अंधी श्रद्धा की वह, बोलना उपदेश बन जाता है। मेरी न तो यह मांग है कि मैं कहता हूं उस पर आप विास करें। न ही मेरा यह कहना है कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है। इतना ही मेरा कहना है कि किसी के भी कहने के आधार पर सत्य को स्वीकार मत करना, और मेरे कहने के आधार पर भी नहीं। सत्य तो प्रत्येक व्यक्ति की निजी खोज है। कोई दूसरा किसी को सत्य नहीं दे सकता। मैं भी नहीं दे सकता हूं, कोई दूसरा भी नहीं दे सकता है। सत्य दिया नहीं जा सकता, पाया जरूर जा सकता है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं, उससे आपको कोई सत्य ही दिखा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। फिर पूछा है कि उपदेश क्यों दे रहा हूं? न ही इसमें मुझे कोई आनंद उपलब्ध होता है कि आप जो मैं कहूं, प्रशंसा करें, उसके लिए तालियां बजाए, उसका समर्थन करें। न ही मेरा यह कोई व्यवसाय है। फिर मैं क्यों कुछ बातें कह रहा हूं। एक आदमी को दिखाई पड़ता हो कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह रास्ता गड्ढों में कांटों में ले जाने वाला है और आपसे कह दे कि इस रास्ते पर कांटे हैं और गड्ढे हैं। वह आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा है। वह केवल इतना कह रहा है कि जिस रास्ते से मैं परिचित हूं उस रास्ते पर उसी गड्ढे में उन्हीं कांटों से किसी को जाते हुए देखना अमानवीय है, चुपचाप देख लेना अमानवीय है, अत्यंत हिंसक कृत्य है। सड़क के किनारे प्रकाश के खंभे लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। जिस आदमी ने सबसे पहले फिल्डेल्फिया में सबसे पहला रास्ते के किनारे का प्रकाश लगाया, वह था बेंजामिन फ्रेंकलिन। बेंजामिन ने सबसे पहले अपने घर के सामने एक बत्ती लगायी, एक खंभा लगाया। पड़ोस में लोगों ने कहा, क्या तुम यह दिखलाना चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम्हारे घर में बड़ा प्रकाश है? यह प्रकाश किसलिए लगाना चाहते हो? बेंजामिन ने कहा, कि नहीं, रास्ते पर ऊबड़-खाबड़ पत्थर हैं, रात में यात्री भटक जाते हैं, कोई गिर भी जाता है, रास्ता खोजना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं एक प्रकाश लगाता हूं कि राह चलने वाले लोगों को मेरे घर के सामने के पत्थर तो दिखाई पड़े, कोई उनसे टकरा न जाए और न गिर जाए।

फोटोग्राफी...

कभी यह एक किला दिखाई पड़ता था।

''अप्रत्याशित'

दिल्ली विविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, जवाहरलाल नेहरू विविद्यालय (जेएनयू) की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद और पांच दीगर मुल्जिम उन झूठे इल्जामों से आखिरकार बरी हो गए हैं, जिसमें उन पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुकमा के एक आदिवासी की हत्या का इल्जाम लगाया था। स्थानीय अदालत में दायर आरोपपत्र में पुलिस ने कहा कि हत्या के मामले में जांच के दौरान इन मुल्जिमों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। ग्रामीणों के बयानों से मालूम चलता है कि हत्या के समय वे वहां मौजूद नहीं थे। लिहाजा उनके खिलाफ सभी मामले वापस लिये जाते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के इस ''अप्रत्याशित' कदम से निश्चित तौर पर इन सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली होगी, जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे थे। बेकसूर होने के बाद भी उन्हें शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा झेलना पड़ी। सारे देश में बदनामी हुई, वह अलग। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 7 नवम्बर 2016 को प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, जोशी अधिकार संस्थान के विनीत तिवारी, माकपा नेता संजय पराते, स्थानीय सरपंच मंजू कवासी और एक ग्रामीण मंगलराम वर्मा के खिलाफ यह कहकर मामला दर्ज कर लिया था कि ये सब लोग सुकमा जिले के नामा गांव के निवासी शामनाथ बघेल की हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और दंगा फैलाने में शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई शामनाथ बघेल की पत्नी के बयान के आधार पर की गई थी। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने जैसे ही यह कार्रवाई की, हंगामा मच गया। पुलिस ने जिन लोगों पर कार्रवाई की, उनमें से कुछ की पहचान लेखक, बौद्धिक चिंतक और मानवाधिकार कार्यकर्ताकी है। समाज में हाशिये से नीचे रहने वाले वंचित तबके और तमाम बहिष्कृत लोगों के बीच यह काम करते रहते हैं। खास तौर से इन लोगों ने अपने लेखन और सामाजिक कार्यवाहियों से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के उत्पीड़न और उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया है। इस मामले में जिस तरह से अचानक कार्रवाई की गई, उससे साफमालूम चलता था कि पुलिस ने दुर्भावना से कार्रवाई की है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुल्जिमों के पास अब एक ही रास्ता बचा था, अदालत। अदालत में मुकदमे के दौरान, दो साल तक पुलिस ने मुल्जिमों से एक बार भी पूछताछ नहीं की। राज्य सरकार इस एफआईआर को लंबित रखे रही। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब-तलब करते हुए उसे फटकारा कि आप अनिश्चितकाल के लिए किसी पर लंबित एफआईआर की तलवार नहीं लटका सकते। तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने इन घटनाओं के लिए माओवादियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इस मामले को वहीं रफा-दफा कर दिया था। लेकिन जब इस मामले को लेकर दिल्ली विविद्यालय की प्राध्यापिका नंदिनी सुंदर और सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश सर्वोच्च न्यायालय पहुंचें और उन्होंने इन घटनाओं के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। अदालत के निर्देश पर जब इस मामले में सीबीआई जांच शुरू हुई तो मामले की पूरी सच्चाई सामने आ गई। आखिरकार तत्कालीन रमन सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि आदिवासियों के उत्पीड़न की इन घटनाओं को विशेष पुलिस अधिकारी और सलवा जुडूम के लोगों ने अंजाम दिया था। यह घटना महज उसका एक छोटा सा नमूना भर है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो, कभी सामने आ ही नहीं पाते, उजागर होने से पहले उन्हें दबा दिया जाता है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 66 रन से हराया

बिष्ट ने इंग्लिश टीम का किया बंटाधार

इस जीत में साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त

मुंबई, (एजेंसी)। अनुभवी लेफ्ट आर्म स्पिनर एकता बिष्ट ने घातक गेंदबाजी करते हुए 25 रन पर चार विकेट लेकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में शुक्रवार को 66 रन से नाटकीय जीत दिला दी। भारत ने इस जीत के साथ तीन मैचों की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

भारत ने 49.4 ओवर में 202 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम एक समय तीन विकेट पर 111 रन बनाकर काफी सुखद स्थिति में थी लेकिन बिष्ट की घातक गेंदबाजी के चलते उसकी पूरी टीम 41 ओवर में 136 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने आखिरी सात विकेट मात्र 25 रन जोड़कर गंवा दिए। इंग्लैंड की तरफ से नताली शिवर ने 66 गेंदों में 44 रन और कप्तान हीथर नाइट ने 64 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए। बिष्ट ने आखिरी छह बल्लेबाजों में से चार को पवेलियन की राह दिखाई। बिष्ट ने आठ ओवर में 25 रन देकर चार विकेट हासिल किए। इनमें से तीन विकेट तो उन्होंने 41वें ओवर में पांच गेंदों के अंतराल में झटके। शिखा पांडे ने 21 रन पर दो विकेट, दीप्ति शर्मा ने 33 रन पर दो विकेट और झूलन गोस्वामी ने 19 रन पर एक विकेट लिया। इससे पहले भारत की पारी में ओपनर जेमिमा रॉड्रिग्स ने 58 गेंदों आठ चौकों की मदद से 48 रन, कप्तान मिताली राज ने 74 गेंदों में चार चौकों के सहारे 44 रन, विकेटकीपर तानिया भाटिया ने 41 गेंदों में 25 रन और झूलन गोस्वामी ने 37 गेंदों में 30 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जॉर्जिया एल्विस, नताली शिवर और सोफी एक्लसटोन ने दो-दो विकेट लिए।

सीओए के अध्यक्ष राय ने बोर्ड अधिकारियों के साथ आम बैठक के बाद कहा...

बीसीसीआई ने सरकार पर छोड़ा आखिरी फैसला

नई दिल्ली। बीसीसीआई ने 30 मई से इंग्लैंड में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। बीसीसीआई का संचालन देख रही प्रशासकों की समिति (सीओए) के अध्यक्ष विनोद राय ने बोर्ड अधिकारियों के साथ शुक्रवार को यहां विशेष आम बैठक के बाद संवादाताओं से कहा कि इस मामले में यदि कोई फैसला लेना है तो भारतीय बोर्ड इसे सरकार के साथ मिलकर लेगा क्योंकि विश्व कप होने में अभी तीन महीने का समय बाकी है। विनोद राय ने कहा कि विश्व कप में 16 जून का भारत और पाकिस्तान का मैच अभी काफी दूर है। हम सरकार के साथ बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि आईसीसी को पुलवामा हमले की जानकारी देते हुए और साथ ही मैनचेस्टर के विश्व कप मुकाबले में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पत्र लिखा जाएगा। सीओए अध्यक्ष ने कहा कि हम इन हमलों को लेकर अपनी चिंता जताते हुए आईसीसी को पत्र लिखेंगे और साथ ही यह बताएंगे कि खिलाड़ियों, अधिकारियों और अन्य सभी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना कितना जरुरी है। हम क्रिकेट समुदाय को बता रहे हैं कि भविष्य में हमें उन सभी देशों से संबंध तोड़ लेने चाहिए जहां से आतंकवादी निकलकर आते है।

विराट, शास्त्री और धोनी से बातचीत करेगा बोर्ड

इस बीच समझा जाता है कि बोर्ड अधिकारी और सीओए विश्व कप में पाकिस्तान से खेलने को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से भी बातचीत करेंगे। बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी के 26 फरवरी को आईसीसी बैठक में इस मुद्दे को उठाने की उम्मीद है। बोर्ड को यह भी डर है कि यदि वह पाकिस्तान के साथ अपना मैच छोड़ने का फैसला करता है तो आईसीसी उस पर भारी जुर्माना लगा सकता है। यह भी माना जा रहा है कि आईसीसी भारतीय बोर्ड की पाकिस्तान की विश्व कप से बाहर करने की मांग को ठुकरा सकता है।

पाकिस्तान मामले में गावस्कर की राह पर चले सचिन

नई दिल्ली। पुलवामा हमले के बाद देशभर में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप नहीं खेले जाने की बहस में क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर भी उतर गए हैं। सचिन ने इस मामले में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की राह पर चलते हुए कहा है कि वह पाकिस्तान को आसानी से दो अंक देने के पक्ष में नहीं है। सचिन ने कहा कि भारत हमेशा विश्व कप में पाकिस्तान से जीता है और एक बार फिर भारत के पास पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में हराने का मौका है। व्यक्तिगत रुप से मैं नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान को बिना लड़े दो अंक मिले। भारत रत्न सचिन ने कहा कि मेरे लिए मेरा देश पहले है। मेरा वतन जो निर्णय लेगा मैं दिल से उस निर्णय का स्वागत करुंगा और अपने देश के साथ रहूंगा।

थरूर ने की पाक के साथ विश्व कप में मैच खेलने की वकालत

नई दिल्ली। क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलने की चौतरफा मांग के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना आत्मसमर्पण से भी बदतर होगा और यह बिना लड़े ही हारने जैसा होगा। थरूर ने विश्व कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की वकालत करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध के समय भी भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेला था। ऐसे में उसके साथ मैच नहीं खेलना आत्मसमर्पण से भी बुरा होगा। थरूर ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय भी भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेला था और जीत भी हासिल की थी। इस वर्ष मैच नहीं खेलने से भारत को सिर्फ दो अंकों का नुकसान नहीं होगा बल्कि यह आत्मसमर्पण करने से भी बदतर होगा क्योंकि यह बिना लड़े ही हार जाने जैसा होगा। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों के मारे जाने के बाद से विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलने की मांग हो रही है। यहां तक कि विश्व कप में पाकिस्तान के खेलने पर रोक लगाये जाने की भी मांग की जा रही है। देश में जहां भारतीय टीम के विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलने की मांग जोरों से उठ रही है पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भी कल कहा था कि भारत को विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए और उसे हराकर विश्व कप से बाहर कर देना चाहिए।

नहीं होगा आईपीएल का उद्घाटन समारोह

नई दिल्ली। एक तरफ जहां आईएसएसएफ विश्व कप का उद्घाटन समारोह डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में मनाया गया वहीं बीसीसीआई ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए आईपीएल के 12वें संस्करण का उद्घाटन समारोह नहीं करने और समारोह के लिए आवंटित राशि को शहीद परिवारों की मदद के लिए देने का फैसला किया है। बोर्ड का मानना है कि पुलवामा आतंकी हमले में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके परिवारों की मदद के लिए कुछ किया जाए। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने इस फैसले का स्वागत करते हुए एक बयान में कहा कि हम आईपीएल का उद्घाटन समारोह रद्द करने और इसके लिए आवंटित राशि शहीदों के परिवारों को देने के फैसला का स्वागत करते हैं। इससे पहले बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि मैं आईपीएल अधिकारियों के इस प्रस्ताव से खुश हूं।

चानू ने जीता स्वर्ण

विशाखापत्तनम। विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण विजेता रेलवे की सैखोम मीराबाई चानू ने अपना वर्चस्व कायम रखते हुए यहां 71वीं पुरुष और 34वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में शुक्रवार को 49 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण विजेता और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीत चुकी मीराबाई चानू ने स्नैच में 83 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 111 किग्रा सहित कुल 194 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की दीपिका (180) को रजत और मणिपुर की एस बिन्दयारानी देवी (172) को कांस्य पदक मिला। महिलाओं के 45 किग्रा वर्ग में दिल्ली की रिया सेन ने कुल 154 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण जीता। महाराष्ट्र की श्रीदीपाली गुसाले (153) को रजत और कर्नाटक की तुष्मिता एमवी (150) को कांस्य पदक मिला। पुरुषों के 55 किग्रा वर्ग में मणिपुर के ऋषिकांत सिंह (239) ने स्वर्ण, महाराष्ट्र के शुभम टोडकर (237) ने रजत और छत्तीसगढ़ के हीरेन्द्र सारंग (236) ने कांस्य पदक जीता।

विदिशा में राज्य स्तरीय क्रिकेट स्पर्धा का शुभारंभ

विदिशा। मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज यहां माधवराव सिंधिया की स्मृति में आयोजित 17वीं राज्य स्तरीय अन्तर अभियांत्रिकीय महाविद्यालयीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ बेटिंग कर किया। एसएटीआई के क्रिकेट ग्राउण्ड पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री सिलावट ने कहा कि खेलो के क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़े। इस ओर संस्थान के द्वारा लगातार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जो अच्छी पहल है। इंजीनियर सदैव जोड़ने का काम करते हैं अति प्राचीन उक्त शैक्षणिक संस्था इंजीनियरिंग के क्षेत्र में राष्ट्र ही नही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलो के माध्यम से अब भविष्य का निर्माण युवाजन कर रहे है। विदिशा जिले में भी खेलो की सुविधाएं पहले की अपेक्षा अब अधिक खिलाड़ियों को मिल रही है निश्चित ही मध्यप्रदेश अब शिक्षा के साथ-साथ खेलो के क्षितिज पर आगे बढ़ रहा है।

हांगकांग में मप्र के सेलिंग खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

भोपाल। हॉन्गकॉन्ग में 12 से 17 फरवरी तक आयोजित एशियन सेलिंग फेडरेशन यूथ कप में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने 11 देशों के खिलाड़ियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। विजेता खिलाड़ियों ने संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ एस एल थाउसेन से भेंट की और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हासिल उपलब्धि से अवगत कराया। डॉ. थाउसेन ने खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शाबाशी और बधाई देकर प्रोत्साहित किया। एशियन सेलिंग फेडरेशन यूथ कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अकादमी के खिलाड़ी राममिलन यादव ने बालक वर्ग के लेजर 4.7 इवेंट में दूसरा और बालिका वर्ग के ऑप्टीमिस्ट इवेंट में अकादमी की खिलाड़ी उमा चौहान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। रीतिका दांगी सातवें स्थान पर रही। प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ी जयदीप ठाकुर और श्रद्धा वर्मा ने भी भागीदारी की। भारतीय टीम में शामिल सात खिलाड़ियों में से पांच खिलाड़ी अकादमी के थे। गौरतलब है कि उक्त खिलाड़ी अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन अवॉर्डी जीएल यादव एवं सहायक प्रशिक्षक अनिल शर्मा से सेलिंग खेल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश ने मणिपुर को किया परास्त

भोपाल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खेली जा रही 9वीं हॉकी इंडिया जूनियर बालक राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप में मध्य प्रदेश हाकी अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मणिपुर हॉकी को 5-0 से हराकर एकतरफा जीत दर्ज कराई। पूल बी में शुक्रवार को खेले गए लीग मुकाबले में अकादमी के खिलाड़ी अली हैदर ने तीसरे मिनट में ही पहला फील्ड गोल दागकर टीम की विजयी शुरुआत की। इसके बाद 9वें मिनट में जर्सी नंबर 9 अली अख्तर ने फील्ड गोल मारकर 2-0 से टीम को आगे कर दिया। मैच के 52वें मिनट में अकादमी के खिलाड़ी अलीशान मोहम्मद ने तथा 54वें और 57वें मिनट में अकादमी के खिलाड़ी अक्षय अवस्थी ने 1-1 फील्ड गोल माल कर टीम को 5-0 से जीत दिलाई। मणिपुर हॉकी टीम का कोई भी खिलाड़ी मैच के अंत तक एक भी गोल नहीं कर पाया।

दिल्ली ने मणिपुर को 10 विकेट से पीटा

विजयवाड़ा। सुबोध भाटी (15 रन पर तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बाद उन्मुक्त चंद (नाबाद 53) और हितेन दलाल (नाबाद 56) की बेहतरीन अर्धशतकों से दिल्ली ने सैयद मुश्ताक अली ट्राफी टी-20 टूर्नामेंट के ग्रुप ए मुकाबले में मणिपुर को शुक्रवार को 10 विकेट से पीट दिया। मणिपुर ने यशपाल सिंह के 50 रन से छह विकेट पर 113 रन बनाए जबकि दिल्ली ने 11.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 119 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल कर ली। उन्मुक्त ने 32 गेंदों पर नाबाद 53 रन में आठ चौके और एक छक्का लगाया जबकि हितेन ने 38 गेंदों पर नाबाद 56 रन में 10 चौके और एक छक्का लगाया।

शशिकिरण और हरिका की जीत से शुरुआत

मॉस्को (रूस)। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट में गिने जाने वाले एरोफ्लोट ओपन में पहला राउंड रद्द होने के बाद अंततः दूसरे दिन पहला राउंड खेला गया और पहले दिन बम होने की खबरों की वजह से दिन भर आपातकालीन स्थितियों में रहने वाले खिलाड़ी दूसरे दिन उसी उत्साह से अपने अपने मैच खेलते नजर आए। भारत के लिहाज से दिन अच्छा रहा है और भारत के शीर्ष खिलाड़ी कृष्णन शशिकिरण ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रूस के क्लेमेंटी सईवेव को पराजित करते हुए प्रतियोगिता की अच्छी शुरुआत की। उनके अलावा सूर्या शेखर गांगुली ने हमवतन प्रग्गनंधा को पराजित करते हुए अपने अभियान की विजय के साथ शुरुआत की। अरविंद चितांबरम, सुनील नारायणन, निहाल सरीन ने जीत के साथ प्रतियोगिता का आरंभ किया।

भारतीय टेनिस टीम 55 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर जाने को है तैयार

कोलकाता। अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) ने कहा है कि भारत डेविस कप के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा और उसने मैच का स्थान बदलने का अनुरोध नहीं किया है। कयास लगाए जा रहे थे कि 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद भारत सितंबर में पाकिस्तान में होने वाले डेविस कप मुकाबले को खेलने से मना कर सकता है। एआईटीए के महासचिव हिरोनमोय चटर्जी ने कहा, 'हमने स्थान को बदलने का अनुरोध नहीं किया है। बाहर मौजूद ऐसी रिपोर्ट निराधार हैं।' डेविस कप में मार्च 1964 के बाद से किसी भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है।

'अगर पाकिस्तान में जाकर नहीं खेले तो हो जाएंगे अयोग्य'

चटर्जी ने कहा, 'मुकाबला अभी भी बहुत दूर है। हम सितंबर में वहां खेलेंगे और फरवरी में ही उस समय की स्थिति (राजनीतिक) का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हम इस मुद्दे पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। मुकाबले पर किसी प्रकार का संदेह नहीं है।' पाकिस्तान टेनिस महासंघ (पीटीएफ) ने इस महीने की शुरूआत में घोषणा की थी कि वे इस्लामाबाद के ग्रास कोर्ट पर भारत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। एआईटीए ने पहले कहा था कि वे मुकाबला खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा वे अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के नियमों के अनुसार अयोग्य हो जाएंगे।

शूटिंग वर्ल्ड कप: भारत की अपूर्वी चंदेला ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक

नई दिल्ली। भारत की महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने राजधानी दिल्ली में चल रहे आईएसएसएफविश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शनिवार को विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। इस भारतीय निशानेबाज ने डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में प्रतियोगिता के पहले दिन 252.9 अंक के शानदार स्कोर से पहला स्थान हासिल किया।

चीन की रूओझू झाओ ने 251.8 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। जबकि चीन की ही एक अन्य निशानेबाज जु होंग (230.4) ने इस स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम किया। अपूर्वी आठ महिलाओं के फाइनल में रजत पदकधारी निशानेबाज से 1.1 अंक आगे रहीं, जिससे उनके दबदबे का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछली विश्व चैम्पियनशिप में टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली अपूर्वी क्वालीफिकेशन में 629.3 अंक से चौथे स्थान पर थीं।

आईओसी का अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के बारे में भारत के साथ सभी चर्चाओं को स्थगित करने का फैसला

पाक निशानेबाजों को वीजा नहीं देने पर भारत के खिलाफ आईओसी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अंतराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप के लिए पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा जारी नहीं किए जाने के बाद अंतराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के बारे में भारत के साथ सभी चर्चाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। गत 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा जारी नहीं करने पर आईओसी ने कड़ा कदम उठाते हुए विश्व कप से पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा के लिए ओलंपिक कोटा की स्थिति को भी रद्द कर दिया है। पाकिस्तानी निशानेबाजों ने इस स्पर्धा में हिस्सा लेना था। आईओसी ने कहा कि जब तक भारत सरकार से लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वह भारत को भविष्य में को ओलंपिक से संबंधित किसी

भी कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं देगा। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद विश्व कप के लिए पाकिस्तानी निशानेबाजों की भागीदारी संदिग्ध हो गई थी। आईओसी का यह फैसला आईएसएसएफ के उस फैसले के कुछ घंटे बाद आया जिसमें आईएसएसएफ के अध्यक्ष व्लादिमीर लिसिन ने कहा था कि इस विश्व कप से 2020 ओलंपिक खेलों के लिए आवंटित किए सभी 16 ओलंपिक कोटा को खत्म किया जाएगा।

आईओसी ने की भारत की आलोचना

विश्व संस्था ने कहा कि आईओसी, आईएसएसएफ और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) तथा भारत सरकार के अधिकारियों के साथ आखिरी समय तक विचार विमर्श के बावजूद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को समय से इस टूर्नामेंट में प्रवेश देने के लिए कोई समाधान नहीं निकल पाया। आईओसी ने ओलंपिक चार्टर के खिलाफ जाने के लिए भारत की कड़ी आलोचना की है। आईओसी ने कहा कि यह स्थिति ओलंपिक चार्टर के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अंतराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले एथलीटों और खेल प्रतिनिधिमंडल के साथ मेजबान देश को किसी भी प्रकार के भेदभाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना समान व्यवहार की गारंटी देनी चाहिए। आईओसी ने भारत सरकार के साथ सभी चर्चाओं को स्थगित करने का फैसला किया है।

विवादों से परे ओलंपिक कोटा पर निशाना साधेंगे निशानेबाज

पाकिस्तान के दो निशानेबाजों को वीजा नहीं मिलने और उनकी 25 मीटर रैपिड स्पर्धा के दो ओलंपिक कोटा समाप्त किए जाने के विवाद से इतर यहां डॉ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 60 देशों के 500 से ज्यादा निशानेबाज शनिवार से हो रहे मुकाबलों में ओलंपिक कोटा पर निशाना लगाने उतरेंगे। विश्व कप में अब 14 ओलंपिक कोटा रह गए हैं जो अगले साल के टोक्यो ओलंपिक के लिए हासिल किए जाएंगे।

राजधानी (न्यू बॉम्बे)	
दिन	रात
246 = 2	160 = 7
139 = 3	127 = 0
शुभांक	
दिन	रात
135 = 9	450 = 9
113 = 5	279 = 8
भाग्यांक	
1 4 7 0	

स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या २४९१ के पार

स्वाईन फ्लू में मौत का आंकड़ा ८५ पर पहुंचा

पिछले २४ घंटे में स्वाइन फ्लू के कई केस दर्ज हुए ७५४ मरीजों अब भी उपचार के तहत : रिपोर्ट में दावा

सूरत। प्रदेश में पिछले चार दिनों से स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या प्रतिदिन १०० से अधिक सामने आ रही है । मरीजों की संख्या २४९१ के पास पहुंच गई हैं और ८५ की मौत भी हो गई । शुक्रवार को एक ही शुक्रवार को एक ही दिन में १०८ मरीजों की पहचान हुई, जबकि तीन की मौत है । स्वाइन फ्लू के सबसे अधिक मरीज अहमदाबाद मनपा क्षेत्र में है । राज्य में पिछले तीन दिनों के आंकड़ो पर नजर डाली जाए तो रोज सौ से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई है । गत २० फरवरी को मरीजों की संख्या ११०, गुरुवार को ११८ और शुक्रवार को १०८ नए मरीजों की पहचान हुई है । शुक्रवार को नए सामने आए मरीजों में से सबसे अधिक ३१ अहमदाबाद मनपा क्षेत्र में है । इसके अलावा सूरत मनपा में १४, वडोदरा मनपा में १३, साबरकांडा जिले में आठ, अमरेली में पांच, जूनागढ़ में चार, भावनगर, आणंद, पाटण, अहमदाबाद जिला और अरवल्ली में तीन-तीन नए मरीज सामने आए है । जबकि महेसाणा, कच्छ, जूनागढ, मपना, खेड़ा और भरूच में दो-दो, गांधीनगर बोटाद, गांधीनगर मनपा, राज कोट, दाहोद, पंचमहाल, वड़ोदरा और सूरत जिलों में स्वाइन फ्लू के एक-एक पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है । इसके साथ ही एक जनवरी से अब तक राज्य में कुल मरीजों की संखअया २४९१ हो गई है । शुक्रवार को तीन मरीजों की मौत के साथ आंकड़ा भी ८२ हो गया है ।

ST बसों की हड़ताल वापस से लोगों को राहत : २८ को बैठक

सूरत। सांतवे वेतन आयोग सहित अपनी विविध मांगों के साथ राज्य भर में ST बस कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित कालीन हडताल का आज दुसरा दिन है। सूरत ST डेपो पर कर्मचारियों द्वारा अपने कपडों को उतार कर प्रदर्शन किया गया। सूरत ST डेपों के 2700 कर्मचारियों भी हडताल कर रहे है।

राज्यभर की एसटी बस सेवा दो दिन की हड़ताल बाद रोजाना के अनुसार शुरू होने से यात्रियों को राहत मिली है । पिछले दो दिन से एसटी बस सेवा बंद रहने की वजह से लोग परेशान हो गये शनिवार को भी एसटी बस सेवा शुरू हो गई है यह बात नहीं मानते हो फिर भी सुबह से ही डिपो पर पूछताछ करते देखने को मिले कई तो खुद पूछताछ करके बस सही में चलेगी कि नहीं इसकी जानकारी ले रहे थे। दूसरी तरफ, सरकार के शासकों और एसटी कर्मचारी यूनियन की संकलन समिति के पदाधिकारियों के साथ बातचीत और उनकी मांगों का समाधान लाने की प्रक्रिया चालू ही है । जिसमें सरकार की तरफ से संकलन समिति की मुख्य मांग सातवां वेतन आयोग के लागू करने को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिए जाने से आखिर में हड़ताल वापस ले ली गई और शनिवार सुबह से राज्यभर में एसटी का व्यवहार रोजाना के अनुसार शुरू हो गया। आगामी २८ मार्च को भी सरकार के साथ संकलन समिति की महत्व की बैठक यह मामले होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि, पिछले दो दिनों के दौरान लंबित प्रश्नों की मांगों के मुद्दे पर राज्यभर के ४५ हजार एसटी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाने से बस सेवा बंद रही, जिसकी वजह से एसटी बस में यात्रा करते लाखों विद्यार्थियों और यात्रियों की परेशानी बढ़ गई थी और उनकी मजबूरी का लाभ लेकर निजी बस या अन्य वाहनचालकों ने दोगुनी से तीन गुनी किराया वसूली गई थी । शनिवार को लोगों ने यात्रा के लिए बाहर निकलने से पहले एसटी बस चालू है कि नहीं यह कंफर्म करना ठीक समझा । राज्य के कर्मचारियों ने झुके बिना आंदोलन चालू रखने से अंत में गत दिन एसटी कर्मचारी की तीन यूनियन के प्रतिनिधियों, एसटी अधिकारियों और मुख्यमंत्री ने बनाई गई कमेटी के सदस्यों और परिवहन मंत्री के साथ एक बैठक होने के बाद देर रात को बारह बजे हड़ताल वापस ले ली गई थी ।

साणंद कांग्रेस बचाओ समिति के विस्फोटक पत्र

बिचौलिए भूमिका निभाने वाले गौतम को सजा के बदले में इनाम

रंगीन मिजाज के सीनियर के विरूद्ध आवाज उठाई गई, कांग्रेस पार्टी में और एक विवाद शुरू हो गया है

अहमदाबाद,२३ फरवरी ।

गुजरात में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई इसकी गंभीर वजह १० से ज्यादा सीटों पर हुई पैसे की तस्करी जिम्मेदार होने की चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करता एक विस्फोटक पत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित के कांग्रेस के पदाधिकारियों को साणंद कांग्रेस बचाओ समिति की तरफ से लिखा गया है । यह पत्र सोशल मीडिया में भी वायरल होने से गुजरात कांग्रेस में फिर एक बार लोकसभा चुनाव पहले ही भारी खलबली मच गई है । पत्र में लगाये गये आरोपों को लेकर गहन जांच की मांग करने से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पहले ही कांग्रेस में आंतरिक विवाद का बड़ा विवाद सामने आया है । साणंद कांग्रेस बचाओ समिति की तरफ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित के कांग्रेस नेताओं को लिखे गये पत्र में बताया गया है कि, अमितभाई यदि अभी कांग्रेस की सरकार होती तो विधायकों को अपने पक्ष में बनाये रखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता ।

गुजरात विधानसभा के चुनाव में भाजपा के विरूद्ध एंटी इन्कम्बन्सी के बीच कांग्रेस पार्टी सत्ता के निकट आकर क्यों हार गई यह यह मामले की निष्पक्ष रूप से सही विश्लेषण किया है क्या कांग्रेस लोगों की वोट की वजह से नहीं हार गई लेकिन कांग्रेस के अंदर ही गद्दार और कांग्रेस की प्रतिष्ठा और कांग्रेस के मंच का कमाई के साधन के तौर पर उपयोग कर लेनेवाले उम्मीदवारों और उनके आसपास घूमने वाले बिचौलिए की भूमिका निभाने वालों ने कांग्रेस को हराया है । वटवा, साणंद सहित दस सीटें ऐसी है जहां पैसे की तस्करी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया है । कांग्रेस को हराने के लिए धनसंग्रह काम करनेवालों को आप हिम्मतपूर्वक सजा दिलाना चाहिए, इसके बदले में इनाम देते हो, साणंद में तीन पार्टियों की ज ग में कांग्रेस की जीत निश्चित मानी जाती थी लेकिन पैसे की तस्करी में दलाल की भूमिका गौतम रावल ने निभायी थी यह बात साणंद का हर व्यक्ति जानता है। आप ऐसा करके एक कमजोर उदाहरण दिया है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है ।

जीएमडीसी ग्राउंड में मोरारीबापू की रामकथा का आयोजन किया गया । जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी उपस्थित हुए ।

बोर्ड की हॉल टिकट सुधारने के लिए पांच दिन का समय

अहमदाबाद,२३ फरवरी ।

गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती कक्षा-१० और कक्षा-१२ की बोर्ड की परीक्षा को अब कुछ ही दिन बाकी रहे है तब विद्यार्थियों को परीक्षा के पहले मिलती हॉल टिकट में भूल होने की कई शिकायत की वजह से भूल सुधारने अब विद्यार्थियों को पांच दिन का समय दिया गया है । कक्षा-१० और कक्षा-१२ की परीक्षा की हॉल टिकट स्कूल को मिलने के पांच दिन में यह सुधार मान्य माना जाएगा । बोर्ड द्वारा यह पूरे मामले में जरूरी कवायद शुरू की गई है। कक्षा-१० और कक्षा-१२ की बोर्ड की परीक्षा आगामी ७ मार्च से शहर की विभिन्न परीक्षा केन्द्र पर शुरू हो रही है ।

प्रहलादनगर क्षेत्र में ४ दुकान के ताले टूटने से सनसनी

अहमदाबाद,२३ फरवरी ।

शहर में चोर इतने बेखौफ हो गये है कि पुलिस के बेखौफ बिना किसी भी जगह पर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं । गत दिन देर रात को चोरों ने प्रहलादनगर रोड पर आनंदनगर के निकट स्थित रिवेरा आर्केड में एक साथ चार दुकानों के ताले तोड़कर १.६० लाख रुपये की चोरी की घटना को अंजाम देने से सनसनी मच गई। धनिक क्षे६ में भी चोर अब चोरी करने से भी डरते नहीं है इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। न्यू राणिप क्षेत्र में स्थित श्यामहिल फ्लेट में रहते और आनंदनगर रोड पर स्थित रिवेरा आर्केड की एक दुकान में चीफ अकाउन्टन्ट के तौर पर नौकरी करते जगदीशभाई गुप्ता ने आनंदनगर पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत की है । रिवेरा आर्केड में स्थित सीपी फीटिंग और टाइल्स की दुकान में जगदीशभाई नौकरी करते है । गुरुवार रात को जगदीशभाई दुकान बंद करके घर गये थे तब चोर ने उनकी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गत दिन सुबह में दुकान में काम करते धीरेनभाई का जगदीशभाई पर फोन आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि दुकान का शटर खुला है। जगदीशभाई ने दुकान के मालिक आदर्शभाई जलान को यह मामले में बात करने पर दोनों लोग दुकान पर पहुंच गये थे। दोनों लोगों ने दुकान में जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था और डीजिटल केश बॉक्स लापता था। डीजिटल केश बॉक्स में डेढ़ लाख रुपया नकद था, जिसे लेकर चोर ले गये। जगदीशभाई और आदर्शभाई ने उनकी दुकान में लगाये गये सीसीटीवी कैमरे के फूटेज देखने पर इसमें चोर के कार्य सामने आय हैं। एक युवक ने शटर खोलकर दुकान में चोरी किए जाने का सामने आया है । जगदीशभाई ने आसपास में जांच किया तो उनको जानकारी मिली कि, रिवेरा आर्केड में दुकान वाले दिलीपभाई ठक्कर (निवासी-सहजानंद बंग्लोज, पालडी) तथा दिनेशभाई कान्तिलाल शेठ (निवासी-वृष्भ सोसाइटी, पालडी) की दुकान में भी शटर तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया था ।

और एक आरोपी विशाल कांबले का नाम सामने

भानूशाली हत्या में इस्तेमाल की गई दो रिवोल्वर जब्त

दोनों शार्प शूटर ने रिमांड के दौरान कबूल करने से नासिक के देवनानी कब्रिस्तान के पीछे छिपाई गई रिवोल्वर जब्त

अहमदाबाद,२३ फरवरी ।

जयंती भानूशाली हत्या केस में फिलहाल में गिरफ्तार हुए दोनों शार्प शूटर की रिमांड के दौरान हुई पूछताछ और कबूल करने के आधार पर हत्या के अपराध में इस्तेमाल की गई दो रिवाल्वर सीट द्वारा जब्त की गई है । फिलहाल में गिरफ्तार किए गए दोनों शार्प शूटर पुलिस रिमांड के दौरान उन्होंने जयंती भानूशाली हत्या केस में अपराध में इस्तेमाल की गई और जिसमें से फायरिंग की गई, यह रिवाल्वर उनको नासिक में वालदेवी नदी के पास देवनानी कब्रिस्तान के पीछे छिपाई थी । रिमांड के दौरान आरोपियों की पूछताछ में यह सच्चाई भी सामने आई थी इस हत्या केस में और एक आरोपी विशाल कांबले का नाम सामने आया है । हालांकि यह एक अपराध में यरवडा जेल में होने से पुलिस ने अब ट्रांसफर वारंट के आधार पर यरवडा जेल से इसे कब्जे में लेने के लिए काम शुरू किया गया है । भानूशाली हत्या केस में कुल पांच गिरफ्तारी हुई है । पांच दिन पहले ही पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर सापूतारा के एक गेस्टहाउस से पूणे के दो शार्प शूटर शशीकांत कांबले और अशरफ शेख को गिरफ्तार कर लिया था । फिलहाल में गिरफ्तार किए गए दोनों शार्प शूटर पुलिस रिमांड के दौरान उन्होंने जयंती भानूशाली हत्या केस में अपराध में इस्तेमाल की गई और जिसमें से फायरिंग की गई, यह रिवाल्वर उनको नासिक में वालदेवी नदी के पास देवनानी कब्रिस्तान के पीछे छिपाई थी । उनकी पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया था कि जयंती भानूशाली की राज नीतिक दुश्मन छबील पटेल ने उनकी हत्या के लिए ३० लाख रुपये की सुपारी दी गई थी । इसके तहत जयंती भानूशाली की हत्या के लिए वह २७ दिसम्बर को अहमदाबाद आया था और भानूशाली की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दोनों छबील पटेल के फार्म हाउस पर ठहरे थे । जांच में यह भी जानकारी सामने आई थी कि, भाजपा के नेता जयंती भानूशाली की हत्या करने वाले दो शार्प शूटरों ने भचाऊ स्टेन पर ब्राउन सुगर का नशा किया था इसके बाद वह ट्रेन में चढ़ गये थे और भानूशाली को गोली मार दी थी । यह मामले में जांच कर रही स्पेशियल इंवेस्टीगेशन टीम की पुलिस जांच में यह सच्चाई सामने आई है । इसके अलावा हत्या करने आये शूटरों के साथ तीसरा व्यक्ति भी था, जिसे पुलिस ने पहचान कर लिया है ।

बोर्ड के उम्मीदवारों-अभिभावकों के लिए समाचार

बोर्ड की परीक्षा के विद्यार्थी को २५ को हॉल टिकट

अहमदाबाद,२३ फरवरी ।

राज्य की शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती कक्षा-१० और १२ की परीक्षा ७ मार्च से शुरू होनेवाली है । इसके पहले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा समाचार आया है । बोर्ड की परीक्षा के लिए विद्यार्थी जिसका इंतजार कर रहे थे, यह समय निकट आ गया है । आगामी २५ फरवरी को सोमवार को शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों में से विद्यार्थी अपनी हॉल टिकट प्राप्त कर सकेंगे । बोर्ड द्वारा राज्य के तय जिले वितरण केन्द्रों पर हॉल टिकट वितरण के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी । शिक्षा बोर्ड द्वारा हॉल टिकट के वितरण के लिए हरएक जिले में स्कूल तय की गई है, जहां से सभी स्कूलों को हॉल टिकट प्राप्त करना पड़ेगा । और इसके बाद विद्यार्थियों को देना पड़ेगा । हमेशा बोर्ड की परीक्षा पहले माता-पिता को किस स्कूल में अपने बच्चे का नंबर आएगा इसे लेकर टेंशन होता है । अभिभावक सहित विद्यार्थी अपना नंबर किस स्कूल में आयेगा इसे लेकर जल्दी होती है । अब शिक्षा बोर्ड ने हॉल टिकट के वितरण की तारीख की घोषणा करके अभिभावकों और विद्यार्थियों का टेन्शन दूर कर दिया है । २५ तारीख को राज्य के सभी जिले के वितरण केन्द्रों पर कक्षा-१०, कक्षा-साइंस और कक्षा-१२ सामान्य प्रवाह की परीक्षा की हॉल टिकट का वितरण स्कूलों को किया जाएगा और इसके बाद विद्यार्थियों को हॉल टिकट का आवंटन किया जाएगा । उल्लेखनीय है कि, अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र में तीन स्कूल तय किए गए है । जिसमें दिवान बल्लूभाई, एयरोमा और तीसरी विद्यालय शामिल है। इस वर्ष कक्षा-१० और कक्षा-१२ की बोर्ड की परीक्षा में करीब १७.२५ लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे ।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)